NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDUSTAN, Delhi, 28.3.2025
Page No. 04, Size:(5.65)cms X (2.09)cms.

छात्रा के उत्पीड़न पर सरकार से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने केरल के कासरगोड जिले में एक छात्रावास में नर्सिंग छात्रा के उत्पीड़न पर राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। आयोग ने चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। छात्रा ने कथित तौर पर वार्डन के उत्पीड़न से तंग आकर अपने छात्रावास के कमरे में आत्महत्या की कोशिश की और तीन महीने कोमा में रहने के बाद उसकी मौत हो गई थी।

NHRC issues notice to state govt

The NHRC on Thursday said it has issued a notice to the Kerala govt and the state's police chief over reports that a nursing student died after three months in coma following an alleged suicide attempt in her hostel room over charges of harassment by a warden in Kasaragod district.

NURSING STUDENT'S SUICIDE

The National Human Rights Commission (NHRC) in a statement observed that the content of the news report, if true, raises a "serious issue of violation of human rights" of the victim.

The student was initially admitted to a private hospital in Mangaluru before being shifted to Kozhikode Medical College where she remained in a critical condition till her death, the statement said.

The right panel said it has, therefore, issued notices to the chief secretary and the director general of police of Kerala, seeking a report within four weeks.

The fellow students have reportedly accused the hostel management of "harassment of the student at workplace", according to the media report carried on March 23. They have alleged that the deceased was "subjected to mental harassment by the hostel warden even when she was not well", it said. PTI

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

AMAR UJALA (MY CITY), Hisar, 28.3.2025
Page No. 2, Size:(13.11)cms X (6.73)cms.

बैठक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर बालकृष्ण गोयल पहुंचे हिसार, बोले-जल्द ही नई वरिष्ठ नागरिक नीति लागू होगी

जेलों में हो रहीं मौतों पर एनएचआरसी ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

माई सिटी रिपोर्टर

हिसार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के विशेष मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने कहा कि किसी भी रूप में मानव अधिकारों का हनन हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं मानवाधिकारों के हनन का मामला दिखे तो इसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

उन्होंने निर्देश दिया कि जेलों में होने वाली मृत्यु के मामलों में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। जेल में एचआईवी और हेपेटाइटिस सहित अन्य टेस्ट नियमित रूप कराएं। कारागारों में बंद कैदियों के सभी आवश्यक दस्तावेज बनाए जाएं। बंदियों के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधा मिले।

उन्होंने वीरवार को लघु सचिवालय में आयोजित संबंधित अधिकारियों की बैठक में बताया कि आयोग में लगभग 92 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया जाता है। आयोग का विशेष फोकस वरिष्ठ नागरिकों पर है, क्योंकि वर्ष 2030 तक हर 6 व्यक्ति में से 1 वरिष्ठ नागरिक होगा। जल्द ही नई वरिष्ठ नागरिक नीति लागू की जाएगी। उन्होंने बैठक के दौरान जिला में चल रहे वृद्धाश्रमों की स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिए कि वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों को पर्याप्त और उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

बैठक में मौजूद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर बालकृष्ण गोयल। स्रोत : प्रशासन

वृद्धाश्रमों की खामियां व लोगों की सूची नियमित करें अपडेट : उन्होंने वृद्धाश्रमों में मृत्युदर, कमियों और वहां रह रहे लोगों की सूची को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए। मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर ने जिला शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में सुझाव बॉक्स लगाए जाएं। पॉश कमेटी का गठन किया जाए।

आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सुझाव बॉक्स सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में नहीं होना चाहिए, ताकि छात्र-छात्राएं निर्भय होकर अपने विचार साझा कर सकें। महिला एवं बाल विकास विभाग को जिले में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि व्यापार करने का अधिकार भी अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में शामिल किया गया है।

HINDUSTAN, Agra, 28.3.2025
Page No. 17, Size:(5.65)cms X (2.09)cms.

छात्रा के उत्पीड़न पर सरकार से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने केरल के कासरगोड जिले में एक छात्रावास में नर्सिंग छात्रा के उत्पीड़न पर राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। आयोग ने चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। छात्रा ने कथित तौर पर वार्डन के उत्पीड़न से तंग आकर अपने छात्रावास के कमरे में आत्महत्या की कोशिश की और तीन महीने कोमा में रहने के बाद उसकी मौत हो गई थी।

DAINIK JAGRAN (JAGRAN CITY), Hissar, 28.3.2025
Page No. 4, Size:(24.90)cms X (14.18)cms.

मानवाधिकार हनन नहीं होगा बर्दाश्त : बालकृष्ण

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मानिटर ने वृद्धाश्रमों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता • हिसार : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मानिटर बालकृष्ण गोयल ने कहा कि किसी भी रूप में मानव अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी स्थान पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो, तो इसकी सूचना आयोग को दें। आयोग की वेबसाइट पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसके लिए किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती।

उन्होंने वीरवार को लघु सचिवालय में आयोजित संबंधित अधिकारियों की बैठक में कही। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दुनिया का सबसे बड़ा आयोग है, जो सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा करता है। उन्होंने बताया कि आयोग में लगभग 92 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया जाता है। विशेष मानिटर बालकृष्ण गोयल ने कहा कि आयोग का विशेष फोकस वरिष्ठ नागरिकों पर है, क्योंकि वर्ष 2030 तक हर छह व्यक्ति में से एक वरिष्ठ नागरिक होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही नई वरिष्ठ नागरिक नीति लागू की जाएगी।

उन्होंने वृद्धाश्रमों की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों को पर्याप्त और उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने वृद्धाश्रमों में मृत्युदर, कमियों और वहां रह रहे लोगों की सूची को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए। मानवाधिकार आयोग के विशेष मानिटर ने जिला शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में सुझाव बाक्स लगाए जाएं। साथ ही, पोश कमेटी का गठन किया जाए और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में करियर काउंसलिंग जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाए। सुझाव बाक्स सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में नहीं होना चाहिए, ताकि छात्र-छात्राएं निर्भय होकर अपने विचार साझा कर सकें।

बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश देते राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मानिटर बालकृष्ण गोयल व अतिरिक्त उपायुक्त सी जयाश्रद्धा व अन्य अधिकारीगण।

चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाए

विशेष मानिटर बालकृष्ण गोयल ने महिला एवं बाल विकास विभाग को जिले में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि जरूरतमंद बच्चों को सुरक्षा और आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। बैठक में उन्होंने जिले के जेलों की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सी जयाश्रद्धा, हिसार एसडीएम ज्योति मित्तल, बरवाला एसडीएम डा. वेदप्रकाश बेनीवाल, हांसी एसडीएम राजेश खोथ, नगर निगम संयुक्त आयुक्त प्रीतपाल सिंह, रोडवेज जीएम डा. मंगल सेन, डीएसपी कमलजीत, डीएसपी सुनील कुमार, डीएसपी रविंद्र सांगवान और सीटीएम हरिराम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

हांसी अस्पताल के इमरजेंसी में घायलों का हालचाल जानते एनएचआरसी के विशेष पर्यवेक्षक बालकृष्ण गोयल • जागरण।

नागरिक अस्पताल व सोरखी सरकारी स्कूल के निरीक्षण में मिली कई खामियां

संवाद सहयोगी, जागरण • हांसी : नई दिल्ली से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष पर्यवेक्षक बाल कृष्ण गोयल ने वीरवार देर शाम करीब साढ़े सात बजे हांसी के नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। सोरखी गांव के सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। वहां पुरानी बिल्डिंग जर्जर हालत में मिली, जबकि नई बिल्डिंग में बच्चों के लिए शौचालय और रैंप की व्यवस्था नहीं थी। स्कूल में लगा फर्स्ट-एड बॉक्स भी एक्सपायरी पाया गया। एसएमसी रजिस्टर में भी कई खामियां मिलीं।

छह दिवसीय दौरा जारी

विशेष पर्यवेक्षक बाल कृष्ण गोयल ने बताया कि उनका छह दिवसीय हरियाणा दौरा चल रहा है, जिसमें गुरुग्राम, हिसार, सिरसा और अंबाला जिलों का निरीक्षण कार्य शामिल है।

चेयरपर्सन को भेजेंगे रिपोर्ट

गोयल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मिली खामियों की रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन को भेजी जाएगी। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PUNJAB KESARI, Hissar, 28.3.2025
Page No. 3, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

मानवाधिकार हनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: बालकृष्ण गोयल

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वृद्धाश्रमों व आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश

बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश देते राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर बालकृष्ण गोयल। साथ में मौजूद अतिरिक्त उपायुक्त सी जयाश्रद्धा व अन्य अधिकारीगण।

हिसार, 27 मार्च (ब्यूरो): राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने कहा कि किसी भी रूप में मानव अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी स्थान पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो, तो इसकी सूचना आयोग को दें। आयोग की वेबसाइट पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसके लिए किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती।

यह बात उन्होंने वीरवार को लघु सचिवालय में आयोजित संबंधित अधिकारियों की बैठक में कही। बैठक में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दुनिया का सबसे बड़ा आयोग है, जो सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा करता है। उन्होंने बैठक के दौरान जिला में चल रहे वृद्धाश्रमों की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों को पर्याप्त और उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी वृद्धाश्रम पंजीकृत हों। उन्होंने वृद्धाश्रमों में मृत्युदर, कमियों और वहां रह रहे लोगों की सूची को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए। मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर ने जिला शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में सुझाव बॉक्स लगाए जाएं। साथ ही, पोश कमेटी का गठन किया जाए और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में करियर काउंसलिंग जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाए। सुझाव बॉक्स सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में नहीं होना चाहिए, ताकि छात्र-छात्राएं निर्भय होकर अपने विचार साझा कर सकें।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सी जयाश्रद्धा, हिसार एस.डी.एम. ज्योति मित्तल, बरवाला एस.डी.एम. डॉ वेदप्रकाश बैनीवाल, हांसी एस.डी.एम. राजेश खोथ, नगर निगम संयुक्त आयुक्त प्रीतपाल सिंह, रोडवेज जी.एम. डॉ मंगल सेन, डी.एस.पी. कमलजीत, सीटीएम हरिराम, सिविल सर्जन डॉ सपना गहलावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Lucknow, 27.3.2025
Page No. 17, Size:(2.54)cms X (9.38)cms.

लघु फिल्म दूध गंगा-वेलीज डाइंग लाइफलाइन को पहला पुरस्कार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बुधवार को 2024 में मानवाधिकारों पर लघु फिल्मों की प्रतियोगिता में सात सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को पुरस्कृत किया। इंजीनियर अब्दुल रशीद भट की फिल्म 'दूध गंगा-वेलीज डाइंग लाइफलाइन' को पहला पुरस्कार मिला है। यह फिल्म इस बात पर चिंता जताती है कि कैसे दूध गंगा नदी में विभिन्न अपशिष्टों के प्रवाहित होने से यह प्रदूषित हुई और घाटी के लोगों की भलाई के लिए इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। यह फिल्म अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में हैं तथा फिल्म के सारे शीर्षक अंग्रेजी में हैं। एनएचआरसी को देश भर से कुल 303 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं थीं।

दूसरा पुरस्कार आंध्र प्रदेश के कदारप्पा राजू की 'फाइट फार राइट्स' को मिला है। यह फिल्म बाल विवाह और शिक्षा के मुद्दे को उठाती है। तीसरा पुरस्कार आर रविचंद्रन द्वारा बनाई गई 'गाड' को मिला है। इस मूक फिल्म में एक बूढ़े नायक के माध्यम से पेयजल का मूल्य बताया गया है।

लघु फिल्म दूध गंगा-वेलीज डाइंग लाइफलाइन को पहला पुरस्कार

- एनएचआरसी ने प्रतियोगिता में सात विजेताओं को किया पुरस्कृत
- देश भर से मानवाधिकारों पर 303 लघु फिल्मों की प्रविष्टियां आईं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बुधवार को 2024 में मानवाधिकारों पर लघु फिल्मों की प्रतियोगिता में सात सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को पुरस्कृत किया। इंजीनियर अब्दुल रशीद भट की फिल्म 'दूध गंगा-वेलीज डाइंग लाइफलाइन' को पहला पुरस्कार मिला है। यह फिल्म इस बात पर चिंता जताती है कि कैसे दूध गंगा नदी में विभिन्न अपशिष्टों के प्रवाहित होने से यह प्रदूषित हुई और घाटी के लोगों की भलाई के लिए इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। यह फिल्म अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में हैं तथा फिल्म के सारे शीर्षक अंग्रेजी में हैं। एनएचआरसी को देश भर से कुल 303 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं थीं।

दूसरा पुरस्कार आंध्र प्रदेश के कदारप्पा राजू की 'फाइट फार राइट्स' को मिला है। यह फिल्म बाल विवाह और शिक्षा के मुद्दे को उठाती है। तीसरा पुरस्कार आर रविचंद्रन द्वारा बनाई गई 'गाड' को मिला है। इस मूक फिल्म में एक बूढ़े नायक के माध्यम से पेयजल का मूल्य बताया गया है। चार लघु फिल्मों को विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इनमें तेलंगाना के हनीश उंद्रमतला की 'अक्षराभ्यासम', तमिलनाडु के आर सेल्वम की 'विलायिला पट्टाधारी' (एन एक्सपेंसिव ग्रेजुएट), आंध्र प्रदेश के मदका वेंकट सत्यनारायण की 'लाइफ आफ सीता' और आंध्र प्रदेश के लोटला नवीन की 'बी ए ह्यूमन' हैं।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम (केंद्र में) और अन्य गणमान्य व्यक्ति बुधवार को मानवाधिकारों पर एनएचआरसी की लघु फिल्म प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए। प्रेट्र

ये पुरस्कार दिल्ली में एनएचआरसी परिसर में आयोजित समारोह में दिए गए। इस अवसर पर एनएचआरसी अध्यक्ष जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन ने संबोधन में कहा कि आयोग का उद्देश्य मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूकता पैदा करना है। मानव अधिकारों पर लघु फिल्म प्रतियोगिता पिछले एक दशक से इस उद्देश्य को बहुत प्रभावी ढंग से पूरा कर रही है। 2015 में जब यह प्रतियोगिता शुरू हुई थी तब केवल 40 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं और अपने 10वें वर्ष 2024 में देश के विभिन्न हिस्सों से 300 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। इससे पता चलता है कि मानवाधिकार जागरूकता के साथ इस आयोजन ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के बीच कितनी लोकप्रियता हासिल की है। इस मौके पर एनएचआरसी सदस्य न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी, विजया भारती सयानी और महासचिव भरत लाल आदि उपस्थित थे।

JANTA SE RISHTA, Online, 28.3.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Janta se Rishta

Andhra: चार तेलुगु लोगों ने मानवाधिकार लघु फिल्म प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते

https://jantaserishta.com/local/andhra-pradesh/andhra-four-telugu-people-win-awards-in-human-rights-short-film-competition-3916707#

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : मानवाधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एनएचआरसी द्वारा आयोजित लघु फिल्म प्रतियोगिता के सात विजेताओं को एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम ने बुधवार को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किए। 'फाइट फॉर राइट्स' नामक लघु फिल्म बनाने वाले आंध्र प्रदेश के कदरप्पा राजू को दूसरे पुरस्कार के रूप में 1.5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और प्रशंसा पत्र मिला। यह फिल्म बाल विवाह और शिक्षा के महत्व पर तेलुगु में बनाई गई थी। 'लाइफ ऑफ सीता' नामक लघु फिल्म बनाने वाले आंध्र प्रदेश के मदका वेंकट सत्यनारायण, 'बी ए ह्यूमन' नामक एक और फिल्म बनाने वाले लोटला नवीन और 'अक्षराभ्यासम' नामक एक और फिल्म बनाने वाले तेलंगाना के हनीश उंद्रमतला को 50-50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार मिला।

DEVDISCOURSE, Online, 28.3.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Devdiscouse

Human Rights Inquiry into Nursing Student's Tragic Death in Kerala

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3324329-human-rights-inquiry-into-nursing-students-tragic-death-in-kerala

The NHRC has addressed allegations of human rights violations following a nursing student's tragic death in Kerala. The student allegedly attempted suicide due to harassment by a hostel warden, leading to a fatal coma. Notices have been issued to Kerala authorities seeking reports on the incident.

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Kerala government and police authorities over the death of a nursing student who was allegedly driven to attempt suicide due to harassment. The incident, reported from Kasaragod district, has raised grave human rights concerns.

The student was initially hospitalized in Mangaluru but was later transferred to Kozhikode Medical College, where she succumbed after spending three months in a coma. The NHRC's intervention seeks to unravel the circumstances that led to this tragic outcome.

The commission has demanded a comprehensive report from the state's chief secretary and the police chief within four weeks. Fellow students have accused the hostel management of subjecting the deceased to continuous mental harassment, even during her illness.

News Laundry

Nearly 25% of India cops back mob violence, 18% think Muslims naturally prone to crime: Report

https://www.newslaundry.com/2025/03/27/nearly-25-of-india-cops-back-mob-violence-18-think-muslims-naturally-prone-to-crime-report

22% of police officials feel killing 'dangerous criminals' is better than a trial, according to a report by Lokniti-CSDS and Common Cause.

One in four police personnel in India support the idea of mobs acting as judge, jury and executioner in matters they consider grave. And 22 percent of police personnel believe that killing 'dangerous criminals' is better than giving them a legal trial.

These are among the findings of a report on the status of policing in India, which was published by Lokniti-CSDS and Common Cause and launched at the India International Centre on Tuesday. The report is based on a survey of 8,276 senior and junior police personnel across 82 locations in 17 states and Union territories, and also includes in-depth interviews with doctors, lawyers, and judges whose jobs involve interacting with the police and people in custody.

The findings paint a grim picture of policing in India, with widespread justification of torture and poor adherence to arrest protocols. The report was unveiled by a panel of experts, including former Odisha High Court Chief Justice S Muralidhar, lawyer and activist Vrinda Grover, public health expert Dr Amar Jaisani, and retired IPS officer Prakash Singh.

Widespread justification of torture

Among the report's most alarming revelations is that 30 percent of police personnel surveyed believe the use of third-degree methods is justified in serious cases, while 9 percent approve of the use even for petty crimes. IPS officers and those handling interrogations were the most likely to condone torture.

Police personnel were also found to justify violence beyond the accused, with 11 percent believing it is acceptable to hit or slap an accused's family members, and 30 percent saying it is sometimes justified. Additionally, 25 percent supported slapping "uncooperative" witnesses, and 9 percent endorsed using third-degree methods against them.

Police personnel overwhelmingly believe that in order to properly fulfil their responsibilities, police should be allowed to use force without any fear of punishment – 26 percent strongly agree and 45 percent somewhat agree.

One out of two police personnel from Jharkhand and Gujarat have a high propensity to justify torture, while those from Kerala are the least likely to justify it.

Twenty-four percent of police personnel claim arrest procedures are rarely or never followed. IPS officers are the least likely to say that these procedures are always complied with, while upper subordinates are the most likely to say so. Compliance varies significantly across states, with Kerala ranked highest at 94 percent and Jharkhand reporting the lowest adherence at 8 percent.

Torture is among the first things to be entirely and explicitly banned in Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights as early as 1948, according to the report. The spirit of protection of fundamental rights in the UDHR is embodied in our Constitution. Like the prohibition of slavery, the prohibition of torture is a jus cogens norm, a fundamental right that cannot be breached by laws or any circumstances, including national emergencies. While most countries have ratified the UN Convention Against Torture, adopted by the UN General Assembly in 1984, by making domestic laws, India has yet to do so, despite past parliamentary deliberations.

Victims mainly from marginalised communities

Interviewees said that the victims of torture are mainly people from poor and marginalised communities. A lawyer described it as “all the faceless and voiceless” are targeted. The report said Muslims, Dalits, Adivasis, people who cannot read and write, and slum dwellers were common targets of torture.

Eighteen percent police personnel feel that Muslims are “naturally prone” to committing crimes to a great extent.

Meanwhile, ten interviewees said they find it is “very rare” to see magistrates interacting with arrested persons. A lawyer described magistrates as “silent spectators” who “do not record anything or ask the arrested persons where and when they were arrested.

Doctors pointed out that medical examinations of arrested persons are often done by doctors without expertise in forensic medicine, who are less able to recognise signs of torture. Examinations are conducted by whichever doctor is available, even if they are an “eye specialist or anaesthesiologist”. Another pointed out that there are no forensic doctors in district and taluk hospitals.

Discrepancies in data and need for training

According to the report, there are discrepancies in the reporting of custodial deaths cases across various data sources. For instance, in the year 2020, the National Crime Records Bureau reports 76 cases, the National Human Rights Commission reports 90 cases, while the National Campaign Against Torture, a civil society initiative, documents 111 cases of custodial deaths in the same year.

The report claimed that a majority of the deaths in police custody occur within 24 hours of arrest. In 2022, as high as 55 percent of the deaths in police custody reported by

NCRB were of persons not on remand, that is those in police custody in the first 24 hours of arrest. In Gujarat, 96 percent of the deaths in police custody that took place between 2018-22 were within 24 hours of arrest.

In 2022, judicial inquiries, which are mandatory in all cases of custodial deaths, were ordered in only 35 percent of the cases. Between 2018 and 2022, cases were registered against police personnel in just 10 percent of the reported deaths in police custody. Of the cases registered, chargesheets were filed in just 12 percent cases. There were zero convictions for deaths in police custody during this period.

According to the survey, 79 percent of police personnel believe that training on human rights is very important. Among the respondents with a high propensity to justify torture, 70 percent feel that training on prevention of torture is very important.

Justice Muralidhar slams NHRC silence, ‘political influence’

After the report’s release, a panel of experts spoke about the findings as well as the need for reforms and accountability for the police force in a session moderated by Suhas Palshikar, chief editor of Studies in Indian Politics. There was some criticism for the report too.

Retired IPS officer Prakash Singh called the findings “painful reading” but defended the use of force in dealing with hardened criminals. He argued that “fear of the police must exist” and criticised the report for focusing excessively on police failures rather than improvements.

Lawyer Vrinda Grover highlighted the lack of legal accountability, pointing out that despite Supreme Court rulings, India has yet to criminalise torture. She noted that the report fails to address sexual violence as a form of police torture, which disproportionately affects women and marginalised groups.

Public health expert Amar Jesani raised concerns about the role of medical professionals in enabling torture, pointing out that autopsy reports are often manipulated to cover up custodial deaths, particularly in cases involving marginalised groups. He also suggested that the survey may have underestimated the true extent of torture due to underreporting.

The key speaker of the discussion, Justice S Muralidhar, delivered a sharp critique of human rights enforcement in India, particularly the NHRC’s failures, the erosion of accountability, and the distortion of language in governance. He began by reading out a letter he was writing to his “friend” and current NHRC chairperson, Justice V Ramasubramanian, questioning the independence of NHRC’s leadership. While the NHRC chairperson is appointed by a committee consisting of the Prime Minister, the Leader of the Opposition, and the Chief Justice of India, he argued that the process remains politically influenced, often favouring candidates aligned with the establishment.

Justice Muralidhar said words like “encounter” have now been sanitised, shifting from a neutral term to a euphemism for extrajudicial killings. He said that governments manipulate language to control narratives, making phrases that once signified human rights concerns now sound suspicious or subversive. He listed 12 methods of police torture documented in the report, including beatings, electric shocks, sexual violence, and psychological abuse, and questioned why NHRC has largely remained silent despite Supreme Court directives against torture.

Justice Muralidhar also called for NHRC’s intervention in protecting marginalised communities, especially sanitation workers, and challenged the commission to address bulldozer demolitions targeting alleged offenders and release statistics to counter claims that it ignores complaints from BJP-governed states.

This report comes amid a ban in India on critically acclaimed film Santosh to hide the reality of police violence and discrimination within the force. But we have a new Sena project to uncover it all. Click here to contribute.

Sakshi Post

Nepali student suicide: NHRC recommends UGC to initiate action against KIIT

https://www.sakshipost.com/news/nepali-student-suicide-nhrc-recommends-ugc-initiate-action-against-kiit-391627

Bhubaneswar, March 27 (IANS) Trouble mounts for the KIIT University in connection with the suicide of a Nepali female student in its campus on February 16 as the National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday recommended the Chairman of University Grants Commission (UGC) to initiate requisite action against the private educational institution and its sister concern Kalinga Institute of Social Sciences (KISS).

The action has been recommended for violating the NHRC guidelines related to sexual harassment and gender sensitisation on the campuses.

The commission on Thursday also asked the chairman of National Assessment and Accreditation Council (NAAC) to examine the issue of violations of UGC guidelines and human rights like anti-ragging, Internal Complaint Committee for sexual harassment at workplace by the KIIT university and submit an Action Taken Report to the commission. Besides, the commission has also directed the Chief Secretary of Odisha to submit ATR on the issue of negligence on the part of the authorities of the private university leading to the suicide of the Nepali student and violations of various constitutional rights of the victim.

The Commissioner of Police, Bhubaneswar-Cuttack Police Commissionerate, has also been asked to submit updated investigation report in the case of girl’s suicide registered at the Infocity police station.

The Apex rights body has issued the recommendations on the basis of the report of NHRC's Spot Inquiry Team which found the authorities of KIIT University violating various constitutional rights of the deceased girl on issues related to sexual harassment and access to higher education, etc.

As per the directions of the commission, the team visited the campus of KIIT University and KISS in Bhubaneswar between March 6 and 8 for an on-spot inquiry into the suicide of Nepali female student and the allegations of various irregularities at the university.

The inquiry team in its report revealed that the deceased Nepali girl student made a complaint on March 12, 2024, to KIIT’s International Relations Office (IRO) in which she had written about undergoing severe mental stress and also had threatened her estranged boyfriend, Advik Shrivastava of committing suicide if he does not delete her objectionable photos.

The team also ascertained that the IRO of university just get undertakings from the victim and the alleged accused and neither referred the issue to the Internal Complaints Committee (ICC) of the institution nor reported the matter at the local police station.

"It is evident that the conduct of the IRO and University officers/disciplinary committee and college authorities sufficient to show that there is gross negligence and omission on their part IRO and University authorities which may treated amount to act of abetment to commit suicide on the part of the university officials, which finally resulted in her suicide," observed the commission.

The Commission also observed that the university officials have admitted the fact that almost 1,000-1,100 students had left their hostel on February 17, whereas almost 180 girl students left the hostel in such a haste which may lead to some other untoward incident, but college authorities did not bothered safety of girl students and they were thrown out from campus.

"Regrettably, the University was unrepentant and even had the audacity to reply that there had been no merit in the allegations. This manifests sheer insensitivity, if not downright arrogance," noted the NHRC.

Besides, the apex rights body also directed the Khordha Collector to submit ATR over the non-compliance of recommendation made by the Khordha Child Welfare Committee on July 6, 2017 regarding irregularities in the (KISS). The CWC had recommended the district collector to form a joint inquiry committee to investigate the irregularities including overcrowding, unclean facilities, and lack of basic amenities at KISS.

Observe Voice

NHRC Celebrates Human Rights Through Film Awards

https://observervoice.com/nhrc-celebrates-human-rights-through-film-awards-105860/

The National Human Rights Commission (NHRC) of India held a significant event in New Delhi today, honoring the winners of its annual short film competition focused on human rights. Justice V. Ramasubramanian, NHRC Chairperson, emphasized the Commission's mission to raise awareness and protect human rights, noting the competition's growth over the past decade. This year, the NHRC received over 300 entries, showcasing a wide array of human rights issues from filmmakers across the country.

Growth of the Competition

Justice Ramasubramanian highlighted the remarkable evolution of the NHRC's short film competition, which began in 2015 with only 40 entries. In its tenth year, the competition attracted more than 300 submissions from diverse regions, including Kashmir and Kanyakumari. This surge in participation reflects a growing awareness of human rights issues among the public. Filmmakers submitted works in various Indian languages, addressing critical topics that resonate with audiences nationwide.

The Chairperson expressed his appreciation for the filmmakers, stating that their contributions are vital in promoting human rights awareness. He encouraged participants to continue creating impactful films that inspire change and foster understanding of human rights challenges in society.

Acknowledging the Award Winners

During the ceremony, Justice Ramasubramanian congratulated the seven award winners, whose films tackled a range of pressing human rights issues. These included environmental concerns like river water pollution, child marriage, education rights, and domestic violence. He praised the filmmakers as “brand ambassadors of human rights,” expressing hope that they would continue to produce meaningful content in the future.

Justice (Dr) Bidyut Ranjan Sarangi, another NHRC member, emphasized the power of film as a medium for advocacy. He specifically mentioned the documentary “Doodh Ganga,” which highlights the pollution affecting the Doodh Ganga River and its implications for the local community. This film, along with others, serves as a call to action for addressing environmental and social issues.

Details of the Awards

NHRC Secretary General Shri Bharat Lal provided an overview of the competition's history, noting the increasing quality and quantity of entries each year. For the 2024

edition, 303 films were submitted, with 243 making it through the initial scrutiny process. A rigorous jury, including NHRC members and senior officials, determined the seven winners.

The first prize of ₹2 lakh was awarded to Er. Abdul Rashid Bhat for his film “Doodh Ganga- Valley’s Dying Lifeline,” which addresses the urgent need to restore the river’s health. The second prize of ₹1.5 lakh went to Kadarappa Raju for “Fight for Rights,” which tackles child marriage and education. The third prize of ₹1 lakh was awarded to R. Ravichandran for “GOD,” a silent film emphasizing the importance of potable water.

Additionally, four films received ‘Certificates of Special Mention,’ each accompanied by a cash prize of ₹50,000. These films included “Aksharabhyasam,” “Vilayilla Pattathari,” “Life of Seetha,” and “Be a Human,” showcasing the diverse range of topics addressed by filmmakers.

Impact of Filmmaking on Human Rights Advocacy

During the event, NHRC members praised the filmmakers for their dedication to storytelling and advocacy. Smt Vijaya Bharathi Sayani remarked on the filmmakers’ commitment to challenging stereotypes and empowering communities through their work. She emphasized that their films contribute to a broader movement for human dignity and justice. The NHRC plans to upload all awarded films on its website, making them available for screening by government departments, educational institutions, and civil society organizations. This initiative aims to further promote human rights awareness and encourage dialogue on critical social issues.   The award winners also shared insights into their creative processes, highlighting the importance of storytelling in raising awareness about human rights. Their films serve as powerful reminders of the ongoing struggle for justice and equality in society.

Construction World

NHRC Honours 2024 Short Film Winners

https://www.constructionworld.in/policy-updates-and-economic-news/nhrc-honours-2024-short-film-winners-/70921

CW Team∆ 2 Min Read 27 Mar 2025 The National Human Rights Commission (NHRC) hosted a special ceremony in New Delhi to honor the winners of its 2024 Short Film Competition on Human Rights. The annual event, which began in 2015 with just 40 entries, has grown significantly, receiving over 300 submissions this year from across the country.

Addressing the gathering, NHRC Chairperson Justice V. Ramasubramanian emphasized the growing importance of human rights awareness through visual storytelling. He commended the seven award-winning filmmakers for their efforts in highlighting pressing human rights concerns, from environmental pollution and education to women's rights and social justice.

Top Award Winners The first prize of Rs 2 lakh was awarded to Doodh Ganga – Valley's Dying Lifeline, directed by Abdul Rashid Bhat from Jammu & Kashmir. The documentary highlights the severe pollution of Kashmir's Doodh Ganga River due to industrial and domestic waste and urges action to restore its pristine condition.

The second prize of Rs 1.5 lakh went to Fight for Rights by Kadarappa Raju from Andhra Pradesh. The film focuses on the prevalence of child marriage and underscores the importance of education in breaking this cycle.

The third prize of Rs 1 lakh was awarded to GOD by R. Ravichandran from Tamil Nadu. This silent film powerfully conveys the importance of potable water through the story of an elderly protagonist.

Special Mentions Four films received Certificates of Special Mention along with a cash prize of Rs 50,000 each:

Aksharabhyasam by Haneesh Undramatla (Telangana)

Vilayilla Pattathari (An Inexpensive Graduate) by R. Selvam (Tamil Nadu)

Life of Seetha by Madaka Venkata Satyanarayana (Andhra Pradesh)

Be a Human by Lotla Naveen (Andhra Pradesh)

Justice Ramasubramanian acknowledged the increasing participation and impact of the competition, noting that the number of entries has grown significantly over the years. He

described the filmmakers as "brand ambassadors of human rights" and encouraged them to continue using cinema as a tool for advocacy.

NHRC Secretary General Bharat Lal highlighted the rigorous three-tier selection process that determined the winners and announced that all award-winning films will be available for public viewing on the NHRC website. These films will also be made accessible for human rights awareness programs conducted by government bodies, academic institutions, and civil society organizations.

The event concluded with the awardees sharing their experiences and the inspiration behind their films, reinforcing the power of cinema in shaping public discourse on human rights.

Tribune

NHRC honours winners of short film competition

https://www.tribuneindia.com/news/delhi/nhrc-honours-winners-of-short-film-competition/

The National Human Rights Commission (NHRC) on Wednesday honoured the seven winners of its 2024 short film competition on human rights, presenting them with awards. Er Abdul Rashid Bhat's film Doodh Ganga- Valley's Dying Lifeline was awarded the first prize...

The National Human Rights Commission (NHRC) on Wednesday honoured the seven winners of its 2024 short film competition on human rights, presenting them with awards.

Er Abdul Rashid Bhat's film Doodh Ganga- Valley's Dying Lifeline was awarded the first prize of Rs 2 lakh along with a trophy and a certificate. The documentary film from Jammu and Kashmir raises concerns about the free flow of various wastes into the pristine water of the Doodh Ganga River. The film also highlighted the need to stop polluting the river and restore it for the overall wellbeing of the people in the Valley. The film is in English, Hindi and Urdu with subtitles in English.

The second prize of Rs 1.5 lakh, along with a trophy and a certificate, was given to Fight for Rights by Kadarappa Raju from Andhra Pradesh. The film raises the issue of child marriage and education. It is in Telugu language with subtitles in English.

The third prize of Rs1 lakh was given to GOD by R Ravichandran, who hails from Tamil Nadu. The silent film underlines the value of potable water.

Four films were also awarded 'Certificate of Special Mention' with a cash award of Rs 50,000 each. These included: Aksharabhyasam by Shri Haneesh Undramatla from Telangana; Vilayilla Pattathari (An inexpensive graduate) by Shri R. Selvam from Tamil Nadu; Life of Seetha by Shri Madaka Venkata Satyanarayana from Andhra Pradesh and Be a Human by Shri Lotla Naveen from Andhra Pradesh.

NHRC chairperson Justice Ramasubramanian said that during the first edition of the competition in 2015, the commission only received about 40 entries. However, in its tenth edition, more than 300 entries were received from different parts of the country in 2024.

"This shows how this event has significantly gained traction as people acroos the county are choosing to make films in various Indian languages, making people aware of various human rights issues," the chairperson stated.

Madhyaman

NHRC issues notice to Kerala govt, police over nursing student's death

https://madhyamamonline.com/kerala/nhrc-issues-notice-kerala-govt-police-nursing-students-death-1393862

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to Kerala's Chief Secretary and Police Chief, seeking a report within a month on the death of a nursing student in Kasaragod.

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Kerala government and the state's police chief over the tragic death of a nursing student, who passed away after being in a coma for three months following an alleged suicide attempt. The incident, which occurred in Kasaragod district, has raised serious concerns about the violation of the victim's human rights. According to media reports, the third-year nursing student attempted suicide in her hostel room amid allegations of harassment by the hostel warden.

The NHRC, taking suo motu cognizance of the matter, highlighted the gravity of the situation and the potential violation of human rights, as reported on March 22. Initially admitted to a private hospital in Mangaluru, the student was later transferred to Kozhikode Medical College, where she remained in critical condition until her death. In response, the NHRC has directed Kerala's Chief Secretary and the Director General of Police to submit a detailed report within four weeks.

Start My Free Trial

Reports from fellow students have accused the hostel management of subjecting the deceased to mental harassment, particularly when she was unwell. The allegations point to the warden's actions contributing to the distress faced by the student at her workplace.

TIMES OF INDIA, Online, 28.3.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Times of India

NHRC issues notice to state govt

https://timesofindia.indiatimes.com/city/thiruvananthapuram/nhrc-issues-notice-to-state-govt/articleshow/119615443.cms

The NHRC on Thursday said it has issued a notice to the Kerala govt and the state's police chief over reports that a nursing student died after three months in coma following an alleged suicide attempt in her hostel room over charges of harassment by a warden in Kasaragod district.

The National Human Rights Commission (NHRC) in a statement observed that the content of the news report, if true, raises a "serious issue of violation of human rights" of the victim.

The student was initially admitted to a private hospital in Mangaluru before being shifted to Kozhikode Medical College where she remained in a critical condition till her death, the statement said.

The right panel said it has, therefore, issued notices to the chief secretary and the director general of police of Kerala, seeking a report within four weeks.

The fellow students have reportedly accused the hostel management of "harassment of the student at workplace", according to the media report carried on March 23.

They have alleged that the deceased was "subjected to mental harassment by the hostel warden even when she was not well", it said. PTI

Free Press Journal

NHRC Takes Suo Motu Cognisance Of Kerala Nursing Student's Suicide Amid Harassment Allegations

https://www.freepressjournal.in/india/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-kerala-nursing-students-suicide-amid-harassment-allegations

The victim was initially admitted to a private hospital in Mangaluru before being shifted to Kozhikode Medical College, where she remained in a critical condition till her death.

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognisance of a media report that on 22nd March, 2025, a third year Nursing student died after three months in coma, following a suicide attempt in the hostel room amidst allegations of harassment by the warden on in Kasaragod district of Kerala.

The victim was initially admitted to a private hospital in Mangaluru before being shifted to Kozhikode Medical College, where she remained in a critical condition till her death.

About The Observation Made

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim student. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Kerala calling for a report in the matter, within four weeks.

According to the media report, carried on 23rd March, 2025, the fellow students have reportedly accused the hostel management of harassment of the student at the workplace. They have alleged that the deceased was subjected to mental harassment by the hostel warden even when she was not well.

In Samachar

NHRC ने केरल के कासरगोड जिले में छात्रावास के वार्डन द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के बीच आत्महत्या के प्रयास के बाद एक नर्सिंग छात्रा की कथित मौत का स्वतः संज्ञान लिया

https://insamachar.com/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-alleged-death-of-a-nursing-student-after-attempting-suicide-amid-allegations-of-harassment-by-hostel-warden-in-kasargod-district-of-kerala/

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें 22 मार्च, 2025 को केरल के कासरगोड जिले में वार्डन द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के बीच छात्रावास के कमरे में आत्महत्या के प्रयास के बाद तीसरे वर्ष की नर्सिंग छात्रा की तीन महीने कोमा में रहने के बाद मृत्यु हो गई। पीड़िता को पहले मंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके बाद उसे कोझीकोड मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां छात्रा की मृत्यु तक उसकी हालत गंभीर बनी रही।

आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह पीड़ित छात्रा के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए, आयोग ने केरल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। 23 मार्च, 2025 को प्रसारित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सहपाठियों ने कथित तौर पर छात्रावास प्रबंधन पर कार्यस्थल पर छात्रा को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मृतका को छात्रावास वार्डन द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद प्रताड़ित किया जाता था।

Janta se Rishta

NHRC ने लघु फिल्म प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया

https://jantaserishta.com/delhi-ncr/nhrc-felicitates-winners-of-short-film-competition-3915482

Delhi दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बुधवार को मानवाधिकारों पर अपनी 2024 लघु फिल्म प्रतियोगिता के सात विजेताओं को सम्मानित किया और उन्हें पुरस्कार प्रदान किए। अब्दुल रशीद भट की फिल्म दूध गंगा- वैलीज डाइंग लाइफलाइन को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ 2 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार दिया गया। जम्मू और कश्मीर की यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म दूध गंगा नदी के प्राचीन जल में विभिन्न अपशिष्टों के मुक्त प्रवाह के बारे में चिंता जताती है। फिल्म ने नदी को प्रदूषित करने से रोकने और घाटी के लोगों की समग्र भलाई के लिए इसे बहाल करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। यह फिल्म अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में है और इसके उपशीर्षक अंग्रेजी में हैं। आंध्र प्रदेश के कदारप्पा राजू की फाइट फॉर राइट्स को 1.5 लाख रुपये का दूसरा पुरस्कार दिया गया, साथ ही एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी दिया गया। फिल्म बाल विवाह और शिक्षा के मुद्दे को उठाती है। यह तेलुगु भाषा में है और इसके उपशीर्षक अंग्रेजी में हैं।

तमिलनाडु के रहने वाले आर रविचंद्रन की फिल्म GOD को 1 लाख रुपए का तीसरा पुरस्कार दिया गया। मूक फिल्म पीने योग्य पानी के महत्व को रेखांकित करती है। चार फिल्मों को 50,000 रुपए के नकद पुरस्कार के साथ 'विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र' से भी सम्मानित किया गया। इनमें शामिल हैं: तेलंगाना के श्री हनीश उंद्रमतला की 'अक्षराभ्यासम'; तमिलनाडु के श्री आर. सेल्वम की 'विलायिला पट्टाथारी' (एक सस्ता स्नातक); आंध्र प्रदेश के श्री मदका वेंकट सत्यनारायण की 'सीता का जीवन' और आंध्र प्रदेश के श्री लोटला नवीन की 'बी अ ह्यूमन'। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम ने कहा कि 2015 में प्रतियोगिता के पहले संस्करण के दौरान आयोग को केवल 40 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। हालांकि, 2024 में इसके दसवें संस्करण में देश के विभिन्न हिस्सों से 300 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं।

अध्यक्ष ने कहा, "इससे पता चलता है कि इस आयोजन ने किस तरह से काफी लोकप्रियता हासिल की है, क्योंकि देश भर के लोग विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्में बनाना पसंद कर रहे हैं, जिससे लोगों को विभिन्न मानवाधिकार मुद्दों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।"

Deccan Herald

Nursing student death case: NHRC issues notice to Kerala govt, state police chief

https://www.deccanherald.com/india/kerala/nursing-student-death-case-nhrc-issues-notice-to-kerala-govt-state-police-chief-3465997

The student was initially admitted to a private hospital in Mangaluru before being shifted to Kozhikode Medical College where she remained in a critical condition till her death.

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday said it has issued a notice to the Kerala government and the state's police chief over reports that a nursing student died after three months in coma following an alleged suicide attempt in her hostel room over charges of harassment by a warden in Kasaragod district.

The NHRC in a statement observed that the content of the news report, if true, raises a "serious issue of violation of human rights" of the victim.
The NHRC has taken suo motu cognisance of a media report that on March 22, "a third-year nursing student died after three months in coma following a suicide attempt in the hostel room amidst allegations of harassment by the warden in Kasaragod district of Kerala", it said.

The student was initially admitted to a private hospital in Mangaluru before being shifted to Kozhikode Medical College where she remained in a critical condition till her death, the statement said.

The right panel said it has, therefore, issued notices to the chief secretary and the director general of police of Kerala, seeking a report within four weeks.

The fellow students have reportedly accused the hostel management of "harassment of the student at workplace", according to the media report carried on March 23.

They have alleged that the deceased was "subjected to mental harassment by the hostel warden even when she was not well", it said.

NDTV

Rights Body Notice To Kerala Officials On Student's Death After NDTV Campaign

https://www.ndtv.com/video/rights-body-notice-to-kerala-officials-on-student-s-death-after-ndtv-campaign-918892

The top human rights body of the country has taken note of the NDTV campaign demanding justice for Chaithanya Kumari, who died on Saturday after attempting to take her life in December. Notices have been issued to the Kerala Chief Secretary and the Director General of Police and they have been asked to submit a report within a month.

In a statement, the Commission said it took suo motu cognisance of the amtter after media reports.

NDTV

Rights Body Notice To Kerala Officials On Student's Death After NDTV Campaign

https://www.ndtv.com/india-news/nhrc-notice-to-kerala-officials-on-nursing-student-chaithanya-kumaris-death-after-ndtv-campaign-8023587

Notices have been issued to the Kerala Chief Secretary and the Director General of Police and they have been asked to submit a report within a month.

New Delhi: The top human rights body of the country has taken note of the NDTV campaign demanding justice for Chaithanya Kumari, who died on Saturday after attempting to take her life in December. Notices have been issued to the Kerala Chief Secretary and the Director General of Police and they have been asked to submit a report within a month.

In a statement, the Commission said it took suo motu cognisance of the amtter after media reports.

"The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights of the victim student. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Kerala calling for a report in the matter, within four weeks," the statement read.

Chaithanya Kumari, a 20-year-old nursing student, had attempted suicide, allegedly after continuous harassment from the warden of a hostel in Kerala's Kasaragod. She had been in a coma since December.

Ranjani, the warden of the hostel belonging to Manzoor Hospital and School of Nursing, will likely be charged for abetment to suicide, investigating officers have said.

The notices to the state's top officials came days after at least two roommates of Chaithanya Kumari made similar allegations against the warden.

Chaithanya's classmates had alleged that the hostel rules were extremely strict. They were denied holidays and barred from using phones, they said.

"According to the media report, carried on 23rd March, 2025, the fellow students have reportedly accused the hostel management of harassment of the student at workplace. They have alleged that the deceased was subjected to mental harassment by the hostel warden even when she was not well," the NHRC STatement read.

The last time Chaithanya was harassed was in December when she returned after a medical check-up. The warden allegedly denied her food and water.

Chaithanya attempted suicide in her hostel room on December 7 and slipped into a coma.

She was initially taken to a private hospital in Mangaluru and then shifted to the city's Kasturba Medical College Hospital.

She was then moved to the Aster Malabar Institute of Medical Sciences in Kannur and then to Kozhikode government medical college, where she died on Saturday.

Onmanorama

Rights panel demands Kerala govt's report on Kasaragod nursing student’s suicide

https://www.onmanorama.com/news/kerala/2025/03/27/kasaragod-nursing-student-death-nhrc-probe.html

Kasaragod: The National Human Rights Commission (NHRC), India's top rights watchdog, has sought a report from the Kerala government on the death of Chaithanya Kumari, a nursing student in Kasaragod.

In a statement issued on Thursday, NHRC, led by retired Supreme Court Justice V Ramasubramanian, said it had sent notices to Kerala's Chief Secretary and State Police Chief, directing them to submit a report on the student's suicide.

The commission took cognisance of a media report stating that Chaithanya, a third-year nursing student, died on March 22 after being in a coma for three months. She attempted suicide on December 7 in her hostel room at Manzoor Hospital & School of Nursing in Kanhangad. Her suicide attempt had sparked violent protests by fellow students and parents, who accused the institution of workplace harassment and enforcing "prison-like conditions" in the school and hostel.

The students alleged they were forced to stay in the on-campus hostel, denied food if they missed dining hours, allowed mobile phone use for only two hours a week (on Sundays), and could step out only for two hours on weekends, accompanied by relatives.

"The commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the victim's human rights," the NHRC statement said. "According to the report, students alleged that the deceased was subjected to mental harassment by the hostel warden, even when she was unwell," it said.

Chief Secretary Sarada Muraleedharan and State Police Chief Shaik Darvesh Saheb have been directed to submit their report within four weeks, that is by April 24.

The Week

SC collegium recommends transfer of Delhi HC judge Dinesh Kumar Sharma to Calcutta HC

https://www.theweek.in/wire-updates/national/2025/03/27/lgd37-sc-collegium-transfer.html

New Delhi, Mar 27 (PTI) The Supreme Court collegium headed by Chief Justice Sanjiv Khanna on Thursday recommended transfer of Delhi High Court judge Dinesh Kumar Sharma to the Calcutta High Court.

The decision was taken at a meeting held by the collegium, which also comprises Justices B R Gavai, Surya Kant, Abhay S Oka and Vikram Nath.

Justice Sharma took oath as a Delhi High Court judge on February 28, 2022.

He joined the Delhi Judicial Service in 1992 and was promoted to Delhi Higher Judicial Service in 2003.

He has also done a course on Conflict Management from University of Oxford, London in distance learning programme while working as Presenting Officer with National Human Rights Commission.

During his judicial career, besides presiding over courts of various jurisdictions, he has worked as Secretary, Delhi High Court Legal Service Committee; Director (Academics) Delhi Judicial Academy; Registrar (Vigilance); Registrar General of Delhi High Court; and Principal District & Sessions Judge, New Delhi.

LIVE 7 TV

कश्मीर में 'दूध गंगा' के प्रदूषण पर बनी लघु फिल्म को मानवाधिकार आयोग का 2024 का प्रथम पुरस्कार

https://live7tv.com/%E0%A4%95%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%A7-%E0%A4%97%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AA/

नयी दिल्ली, 26 मार्च (लाइव 7) इंजीनियर अब्दुल रशीद भट की फिल्म 'दूध गंगा-घाटी की मरती हुई जीवन रेखा' को मानवाधिकार संबंधी विषयों पर लघु फिल्मों के लिए 2024 का भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिाकर आयोग (एनएचआरसी) का दो लाख रुपये का पहला पुरस्कार दिया गया है।

एनएनआरसी ने बुधवार को राजधानी में अपने परिसर में 2024 में मानवाधिकारों पर अपनी लघु फिल्म प्रतियोगिता के सात विजेताओं को सम्मानित करने और पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक समारोह आयोजित किया।

समारोह को संबोधित करते हुए, एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. सुब्रमण्यम ने कहा कि आयोग का उद्देश्य मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जागरूकता पैदा करना है। मानवाधिकारों पर इसकी लघु फिल्म प्रतियोगिता पिछले एक दशक से इस उद्देश्य को बहुत प्रभावी ढंग से पूरा कर रही है। इस अवसर पर एनएचआरसी के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी और विजया भारती सयानी, महासचिव भरत लाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एनएचआरसी, भारत के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह ने पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की। जम्मू-कश्मीर की प्राचीन दूध गंगा नदी प्रदूषण के मुद्दे को उजागर करते वृत्त चित्र ' गंगा-घाटी की मरती हुई जीवन रेखा' को प्रथम पुरस्कार की घोषणा की गयी। इस फिल्म में कश्मीर घाटी के लोगों की समग्र भलाई के लिए इस नदी को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता को रखांकित किया गया है। फिल्म अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में है और इसके उपशीर्षक अंग्रेजी में हैं।

इसी तरह 1.5 लाख रुपये का दूसरा पुरस्कार, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र आंध्र प्रदेश के कदारप्पा राजू की 'फाइट फॉर राइट्स' को दिया गया। फिल्म बाल विवाह और शिक्षा के मुद्दे को उठाती है तमिलनाडु के आर. रविचंद्रन द्वारा 'गॉड' को एक लाख रुपये, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र दिया गया। मूक फिल्म में एक बूढ़े नायक के माध्यम से पीने योग्य पानी के मूल्य को बढ़ाया गया है।

कार्यक्रम में चार फिल्मों को 'विशेष उल्लेख का प्रमाण पत्र' प्रदान किया गया, जिसमें प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए गए। इनमें शामिल हैं: तेलंगाना के हनीश उंद्रमतला की 'अक्षराभ्यासम'; तमिलनाडु के आर. सेल्वम की 'विलायिला पट्टाथारी (एक सस्ता स्नातक)'; आंध्र प्रदेश के मदका वेंकट सत्यनारायण की 'सीता का जीवन' और आंध्र प्रदेश के लोटला नवीन की 'मानव बनें'।

LIVE NEWS, Online, 28.3.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

पुरस्कार विजेताओं ने अपनी पुरस्कार विजेता लघु फिल्मों के निर्माण के पीछे के विचारों को भी साझा किए।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PRINT, Online, 28.3.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

The Print

नर्सिंग छात्रा मौत मामला: केरल सरकार और राज्य पुलिस प्रमुख को एनएचआरसी का नोटिस

https://hindi.theprint.in/india/nursing-student-death-case-nhrc-notice-to-kerala-government-and-state-police-chief/800343/

नयी दिल्ली, 27 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने केरल सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को उन रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया है, जिनमें कहा गया है कि कासरगोड जिले में एक वार्डन द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के चलते अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या के प्रयास के बाद तीन महीने कोमा में रही एक नर्सिंग छात्रा की मौत हो गई।

एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि यदि समाचार रिपोर्ट की विषय-वस्तु सही है तो यह पीड़िता के 'मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा' उठाती है।

एनएचआरसी ने 22 मार्च को मीडिया में आई एक रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि 'केरल के कासरगोड जिले में वार्डन द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के बीच छात्रावास के कमरे में आत्महत्या के प्रयास के बाद तीसरे वर्ष की एक नर्सिंग छात्रा की तीन महीने तक कोमा में रहने के बाद मौत हो गई।'

बयान में कहा गया है कि छात्रा को पहले मंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके बाद उसे कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां मौत तक उसकी हालत गंभीर बनी रही।

इसलिए, समिति ने केरल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

IBC24, Online, 28.3.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

IBC24

नर्सिंग छात्रा मौत मामला: केरल सरकार और राज्य पुलिस प्रमुख को एनएचआरसी का नोटिस

https://www.ibc24.in/country/nursing-student-death-case-nhrc-issues-notice-to-kerala-govt-state-police-chief-3004124.html

नयी दिल्ली, 27 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने केरल सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को उन रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया है, जिनमें कहा गया है कि कासरगोड जिले में एक वार्डन द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के चलते अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या के प्रयास के बाद तीन महीने कोमा में रही एक नर्सिंग छात्रा की मौत हो गई।

एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि यदि समाचार रिपोर्ट की विषय-वस्तु सही है तो यह पीड़िता के 'मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा' उठाती है।

एनएचआरसी ने 22 मार्च को मीडिया में आई एक रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि 'केरल के कासरगोड जिले में वार्डन द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के बीच छात्रावास के कमरे में आत्महत्या के प्रयास के बाद तीसरे वर्ष की एक नर्सिंग छात्रा की तीन महीने तक कोमा में रहने के बाद मौत हो गई।'

बयान में कहा गया है कि छात्रा को पहले मंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके बाद उसे कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां मौत तक उसकी हालत गंभीर बनी रही।

इसलिए, समिति ने केरल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

The Print

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंधन पर दिशानिर्देश जारी किए

https://hindi.theprint.in/india/health-ministry-issues-guidelines-on-medical-oxygen-management/800345/?amp

नयी दिल्ली, 27 मार्च (भाषा) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने मेडिकल ऑक्सीजन बुनियादी ढांचे के समुचित रखरखाव और उपयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

सलिला दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एक कार्यशाला में बोल रही थीं, जिसमें ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य 200 “मास्टर प्रशिक्षकों” को प्रशिक्षित करना है जो देश भर में अस्पताल प्रशासकों और चिकित्सा अधिकारियों की क्षमता निर्माण की दिशा में काम करेंगे, ताकि मेडिकल ऑक्सीजन के उचित संचालन और उपयोग, अपव्यय को कम करने और क्लीनिकल परिणामों में सुधार लाया जा सके।

कार्यशाला में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सलिला ने कहा कि किसी स्वास्थ्य सेवा सुविधा में क्षमता में किसी भी वृद्धि की स्थिति में जरूरतों को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के बुनियादी ढांचे को बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के भारत के प्रबंधन से सीख लेने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

एम्स निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम की अगुवाई करने में संस्थान की भूमिका पर प्रकाश डाला और स्वास्थ्य सेवा के सभी स्तरों पर प्रशिक्षण और जागरूकता के महत्व पर बल दिया।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी करना देश के मेडिकल ऑक्सीजन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्वास्थ्य सुविधाओं में ऑक्सीजन प्रबंधन में एक समान सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।